<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 1250

11 फरवरी, 2019 को उत्तर के लिए

इस्पात परियोजनाएं

1250. श्री केसिनेनी श्रीनिवासः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस्पात संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है तथा कितनी इस्पात परियोजनाओं पर देश में अभी कार्य चल रहा है;

(ख) क्या इस्पात संयंत्रों की वर्तमान संख्या देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस्पात आयात के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ओडिशा, गोवा और कर्नाटक राज्यों में लोहे के खनन/उत्पादन की सीमा निर्धारित करने के कारण इस्पात के उत्पादन में गिरावट आई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में उपयुक्त और विनिर्मित इस्पात का कुल प्रतिशत तथा आयातित इस्पात का प्रतिशत कितना है; और

(ङ) क्या विगत कुछ वर्षों से इस्पात के आयात में वृद्धि हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे घरेलू बाजार और स्वदेशी इस्पात संयंत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका सुविधाप्रदाता तक सीमित होती है। नए इस्पात संयंत्र की स्थापना अथवा इस्पात संयंत्र में नई परियोजना को आरंभ करने के संबंध में निर्णय अनिवार्य रूप से संबंधित कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं, जो वाणिज्यिक सोच-विचार और बाजार गतिशीलता पर आधारित होते हैं। भारत में दो प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियाँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) है। सेल के इस्पात संयंत्र नामशः भिलाई इस्पात संयंत्र (छत्तीसगढ़), दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल), राउरकेला इस्पात संयंत्र (ओडिशा), बोकारो इस्पात संयंत्र (झारखंड), इस्को इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल) और तीन विशेष इस्पात संयंत्र नामशः अलॉय इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल), सेलम इस्पात संयंत्र (तमिलनाडु) तथा विश्वेश्वरैया लोहा एवं इस्पात संयंत्र (कर्नाटक) है और आरआईएनएल का विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में इस्पात संयंत्र है।

अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान फिनिश्ड इस्पात का सकल उत्पादन, घरेलू खपत और फिनिश्ड इस्पात का आयात (अलॉय एवं नॉन-अलॉय) निम्नवत तालिका में दिया गया है:-

(हजार टन में)

	सकल उत्पादन	**आयात**	**खपत**
अप्रैल-दिसंबर 2018	97598	5910	71551
अप्रैल-दिसंबर 2017	93177	6096	66301
% वृद्धि	**4.7%**	**-3.1%**	**7.9%**

[स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)]

उपर्युक्त आंकड़ों द्वारा सुझाव दिया गया है कि इस्पात उत्पादन का वर्तमान स्तर घरेलू माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

बाजार दबावों के आधार पर आयात के लिए विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में स्टील के कुछ उच्च ग्रेडों की अनुपलब्धता यथा उच्च ग्रेड ऑटोमोटिव स्टील, इलेक्ट्रिकल स्टील, एपीआई स्टील के उच्चतर ग्रेड इत्यादि शामिल है।

(ग): जी नहीं। फिनिश्ड इस्पात के सकल उत्पादन में अप्रैल-दिसंबर 2017 की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2018 में 4.7% की वृद्धि को दर्शाया गया है।

(घ):

	2017-18	**2018-19 (अप्रैल-दिसंबर)**
फिनिश्ड इस्पात खपत (एमटी)	90.61	71.55
फिनिश्ड इस्पात उत्पादन (एमटी)	104.97	97.60
फिनिश्ड इस्पात आयात (एमटी)	7.48	5.91
कुल खपत के % रूप में फिनिश्ड इस्पात आयात	**8.3%**	**8.3%**

(स्रोत: जेपीसी)

(ङ): वर्ष 2017-18 में फिनिश्ड इस्पात के आयातों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 3.6% तक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में अप्रैल-दिसंबर 2018 की अवधि में आयातों में विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में ~3.1% तक की गिरावट आयी है।

	2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19 (अप्रैल-दिसंबर)**
फिनिश्ड इस्पात आयात (एमटी)	8.72	7.22	7.48	5.91

(स्रोत: जेपीसी)

भारत में इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, अतएव सरकार देश में इस्पात उत्पादों के मुक्त और उचित व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करती है। तथापि, भारत सरकार ने किसी भी प्रकार के अनुचित व्यापार से भारत में आने वाले सस्ते आयातों से घरेलू इस्पात क्षेत्र को होने वाली हानि से बचाव के लिए कई डब्ल्यूटीओ अनुवर्ती व्यापार उपचारात्मक उपाय किए हैं। सरकार द्वारा किए गए इन उपायों के कारण भारत में अनुचित व्यापार आयातों में कमी हुई है।

****